and bulk consumers are also advised from time to time to take similar preventive action. Quality control measures are taken right from the raw water stage upto the consumers end, including random checking of 250—300 samples daily.

दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस्तों का भुगतान न किया जाना

1341. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब वर्गों के लिए बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता फ्लैटों के संबंध में किस्तों का भुगतान न करने पर लगाये गये भारी जुर्मानों को माफ करने संबंधी घोषणा को लागू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम "हायर परवेज पेनल्टी रिलीफ स्कीम 96" के अंतर्गत जुर्मने की राशि में दो तिहाई छूट दी गई थी जिसे बाद में घटा दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार दो तिहाई या उससे अधिक राशि की छूट की घोषणा कब तक करेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डीडीए के जनता फ्लैटों की किश्तों का भुगतान न करने के कारण लगाए गए भारी जुर्माने में रियायत देने संबंधी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) डीडीए ने जुर्माना रियायत स्कीम 1995 और 1996 शुरू की थी जिससे तहत क्रमशः 66% और 50% रियायत दी गई थी। दूसरी, जुर्माने रियायत स्कीम, 1997 शुरू की गई जिसके अन्तर्गत जिन आबंटियों ने 30.9.97 तक बकाया राशि जमा कर दी थी उन्हें जुर्माने में 43% रियायत दी गई तथा जिन आबंटियों ने बकाया राशि 1.10.97 से 31.12.97 तक जमा की उन्हें 37% रियायत दी गई। जुर्माना रियायत स्कीम को 30.6.98 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जुर्माने में 37% रियायत दी जा रही है। जुर्माने में रियायत देने की दूसरी कोई भी स्कीम डीडीए में विचाराधीन नहीं है।

Towns Covered under UAWSS in Maharashtra

1342. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the towns which are covered under the Urban Accelerated Water Supply Scheme in Maharashtra State;

(b) the salient features of the scheme; and

(c) the number of such schemes sponsored by Government of Maharashtra and how many have got for approval from Government?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) is applicable to towns having population less than 20,000 as per 1991 census.

(b) The focus of the scheme is to provide water supply to the smaller towns which have lower economic base and which were not being given priority by the State Governments. While approving the scheme, efforts are made to ensure that the unserved population of the town is provided with safe drinking water, 95% dependability and reliability of water source is established and plan for sustainable operation and maintenance is evolved. The scheme is funded by the Central/State Governments on an equal sharing basis.

(c) The Government of Maharashtra has forwarded 29 schemes, out of which 10 schemes at an estimated cost of Rs. 1371.10 lakhs involving Central share of Rs. 685.55 lakhs have been approved.

लक्ष्मीबाई नगर में झुग्गियां

1343. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्ष्मीबाई नगर में बारात घर से दिल्ली हाट तक और डिस्पेंसरी के पीछे झुग्गियों की संख्या में

लगातार वृद्धि हो रही है और इसके कारण कालोनी का वातावरण दूषित हो रहा है और कूड़े के कारण पालिका ग्राम रोड पर चलना दूभर हो गया है;

(ख) सरकार इन झुग्गियों को शीघ्रातिशीघ्र हटाने के लिए, और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है; जिनकी लापरवाही से इस क्षेत्र में ये झुग्गियां बन चुकी या बन रही हैं;

(ग) इस क्षेत्र में वृक्षारोपण न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार नवयुग स्कूल के सामने एक उद्यान बनाने का विचार रखती है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां। झुग्गियों की संख्या बढ़ रही है।

(ख) से (घ) भूमि तथा विकास कार्यालय के अनुसार संबंधित भूमि को "ग्रीन एरिया" अधिसूचित किया गया है और सुरक्षा तथा रख-रखाव की दृष्टि से इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। भूमि तथा विकास कार्यालय ने संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा क्षेत्र को हरा-भरा बनाए रखने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ मामले का उठाया गया है।

Privatising the Municipal Water Supply and Sewage Management in Major Cities

1344. SHRIMATI MALTI SHARMA: PROF. RAM KAPSE:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the World Bank has suggested to Government to privatise the municipal water supply and sewage management in major cities;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto;

(c) whether Government have consulted the State Government on the subject; and

(d) if so, what is the consensus of opinion of the State Government?

2472/RS/98

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) and (b) No, Sir. However, the World Bank has carried out a study on Water Resources Management sector in India in collaboration with the Ministry of Water Resources. As part of this, a study was taken up by the World Bank for the Urban Water Supply and Sanitation sector in collaboration with this Ministry. The draft study report, which is under finalisation by the World Bank, indicates the need for State owned water utility and sanitation agencies to undertake reforms, which may vary from State to State and may lead in some cases to privatisation. The report also suggests that institutional reforms should be supported especially by enhancing private sector participation to enhance efficiency and improve service delivery. It is the policy of the Government to encourage private sector participation in infrastructure development.

(c) and (d) Some of the State Governments and major Urban Water Supply and Sanitation agencies had been requested to furnish certain basic information/data and were consulted by the study team. The State Governments and some of the major Urban Water Supply and Sanitation agencies were invited to participate in National Workshop organised by this Ministry in collabortion with the World Bank at New Delhi on 9-10 June, 1997 to discuss the strategies to be incorporated in the study report referred to above.

Swamy Daya Nand Colony, New Delhi

1345. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the DDA (Slum) has sent revised demand notices to the allottees/occupants of Swami Daya Nand Colony, Sarai Rohilla, Delhi;

(b) if so, the number of allottees to whom notices have been sent so far;